International Journal of Sociology and Humanities
www.sociologyjournal.net
Online ISSN: 2664-8687, Print ISSN: 2664-8679
Received: 01-08-2021, Accepted: 04-09-2021, Published: 03-10-2021
Volume 3, Issue 1, 2021, Page No. 29-30

ग्रामीण समाज मे, आर्थिक एवं राजनैतिक का स्वरूप

रिंकी कुमारी

गवेषिका, समाजशास्त्र विभाग, ल०ना०मि० विश्वविद्यालय, कामेष्वरनगर, दरभंगा, बिहार, भारत

प्रस्तावना

ग्रामीण समाज के आर्थिक क्षेत्रों में पिछले 60–70 वर्षों में क्रान्तिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। यदि एक ओर ग्राम–उद्योगों और कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ है तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण भी हुआ है। स्वतंत्रता के बाद लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास छोटे–बड़े कारखाने और उद्योग स्थापित हुए हैं। इसमें करोड़ों की संख्या में ग्रामीण अपना कृषि कार्य छोड़कर नौकरी करने लगे हैं। इसका एक प्रभाव यह भी हुआ कि करोड़ों की संख्या में ग्रामीण परिवार नगरों या आसपास के क्षेत्रों में जाकर बस गये हैं। इससे एक ओर उनकी आय में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर उनके जीवन सार में सुधार हुआ है। कृषि के लिए अब गये नये प्रकार के उन्नत बीज, खाद और बड़ी–बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है जिससे न केवल फसलों का उत्पादन बढ़ा है बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है।[1]

आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन होने से समाज के विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। कार्ल्स मार्क्स का यह विचार है कि आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन होने से समाज की सभी चीजों में परिवर्तन स्वतः ही होते हैं। उसका यह वृढ़ विश्वास है कि उत्पादन के साधनों के अनुरूप ही सामाजिक ढाँचे का निर्माण होता है और यदि उत्पादन के साधन परिवर्तित होते हैं तो उसका प्रभाव धार्मिक जीवन पर भी पड़ता है।[2] ग्रामीण समाज के आर्थिक जीवन में निम्न परिवर्तन होते हुए देखा जा सकता हैः

1. **औद्योगीकरण और मशीनीकरण :** औद्योगीकरण और मशीनी क्रान्ति ने गाँव के आर्थिक ढाँचे में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न किया है। औद्योगीकरण ने मशीनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक क्रांति को जन्म दिया है। ग्रामीण व्यक्ति भी भौतिकवादी और महत्वाकांक्षी हुआ है। इस क्रान्ति ने व्यक्ति को अधिक से अधिक धन अर्जन करने की प्रेरणा दी है।
2. **आय में वृद्धि :** ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति अब कृषि पर ही निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अतिरिक्त आय के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को भी करते हैं। खाली महीनों और समय में वे नगरों में आकर कोई न कोई कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि व्यवसाय में वैज्ञानिक ढंग से खेती करने लगे हैं जिससे उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हरित क्रान्ति ने उनकी आय में वृद्धि की है। इससे ग्रामीण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अभी भी निम्नवर्ग और भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति दयनीय है।
3. **वर्गों की उत्पत्ति :** औद्योगिक और मशीनीकरण ने ग्रामीण समाज में भी वर्गों को उत्पन्न किया है। निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग आज सरलता से अनेक गाँवों में देखे जा सकते हैं। वर्गों के मध्य भी निरन्तर संघर्ष है कि वे अपने वर्ग से उच्च वर्ग में प्रवेश करे। हमारी सरकार भी निरन्तर यह प्रयत्न कर रही है कि निम्न वर्ग, पिछड़े वर्ग, हरिजन और जनजातीय वर्ग को अधिक से अधिक सुविधायें दी जाय जिससे वे अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके ।
4. **श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया :** सभी समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में देखी जा सकती है किन्तु प्रौद्योगिकरण और वैज्ञानिक प्रगति ने परम्परागत श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया के स्थान पर उसको नवीन स्वरूप प्रदान किया है। ग्रामीण समाज में जाति के आधार पर श्रम विभाजन और विशेषीकरण की पद्धति अब दिन–प्रतिदिन लचीली होती जा रही है। नए उद्योगों के आधार योग्यता और कुशलता है। इसने ग्रामीण व्यक्तियों को कुशल और दक्ष कारीगर होने की प्रेरणा दी है।
5. **जीवन स्तर में परिवर्तन :** उद्योग और विज्ञान के विकास के कारण व्यक्तियों के जीवन स्तर में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए द्य अस्तु गाँव के छोटे से छोटे परिवार में भी टेलीविजन, कुर्सी, मेज, कप–प्लेट तथा अन्य आधुनिक चीजों को देखा जा सकता है। इसी तरह खान–पान, वस्त्र आदि के प्रयोग में भी बदलाव आया है जैसे सामान्य व्यक्ति भी मँहगें कपड़ों को पहनने लगा है। स्त्रियाँ आधुनिक कपड़े पहनने लगी है साथ आधुनिक श्रृंगार का इस्तेमाल करने लगी है।
6. **नियोजन द्वारा परिवर्तन :** ग्रामीण आर्थिक ढाँचे को सुनियोजित ढंग से परिवर्तित करने का श्रेय पंचवर्षीय योजनाओं को है। सामुदायिक विकास योजनाएँ, सहकारी समितियाँ, ग्रामीण बैंक, प्रोत्साहन, सिंचाई और बिजली की सुविधायें, सरकारी ऋण व्यवस्थाओं ने कुटीर उद्योग धन्धों को परिवर्तित कर दिया है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण समाज के व्यक्तियों के रहन–सहन, सोचने–विचारने और काम करने के ढंग में काफी परिवर्तन हुए है। इन योजनाओं ने ग्रामीण व्यक्तियों की मानसिक और परम्परात्मक सोच को बहुत कुछ बदलने का श्रेय प्राप्त किया है।[3]

ग्राम का राजनैतिक परिवर्तन

शताब्दियों पुरानी सामन्ती और जमींदारी प्रथा स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ समाप्त हो गयी। संपूर्ण राजनैतिक शक्ति सामन्तों और जमींदारों में केन्द्रित थी। इसके संकेत पर ही गाँव में पत्ता डोलता था। ये धनी भी थे और सवर्ण भी। राजनीति पर इनका जन्म – जात अधिकार और अंकुश था। स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारी समाप्त हुई। सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ। पंचायतों को पुनर्निर्माण किया गया। चुनाव के माध्यम से इसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। गाँव– प्रधान का लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होता है। किसी भी जाति का व्यक्ति गाँव– प्रधान बन जाता है बशर्ते वह चुनाव में जीत जाय।

ग्रामीण समाज में एक नहीं अनेक राजनैतिक दल है। प्रत्येक दल के हजारों लाखों सदस्य हैं। उन्हीं दलों के एम.एल.ए., एम.पी. और मंत्री भी हैं। गाँव की राजनीति अब किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है वरन् उसमें भाग लेने का भी सभी को समान अधिकार है। हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों को राजनीति में कुछ विशेष सुविधाएँ दी गयी हैं जो संवर्णों को भी प्राप्त नहीं है। इनके कुछ स्थान विधान सभा और संसद में सुरक्षित हैं जिन पर इन्हीं जाति के व्यक्ति चुनकर जाते हैं। इस तरह ग्रामीण समाज जो स्वतंत्रता से पूर्व राजनैतिक योजना में लगभग शून्य था आज राजनैतिक चेतना गाँव–गाँव पहुँच चुकी है। आज ग्रामीण व्यक्ति भी अपने दल और दलगत भावना के अनुसार राजनैतिक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करता है। यह ग्रामीण राजनैतिक चेतना में बदलव को दर्शाते हैं।

स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन के प्रतिमान में चतुर्मुखी परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन ग्रामीण समाज के आर्थिक, और राजनैतिक ढाँचे को परिवर्तित कर रहे हैं। ये परिवर्तन जहाँ औद्योगीकरण और नगरीकरण की देन है वहीं सरकार की नियोजित पंचवर्षीय योजनाओं की भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका है। गाँव के आर्थिक ढाँचे और स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। पहले की अपेक्षा व्यक्तियों की आर्थिक और राजनैतिक जीवन में सुधार हुआ है। गाँव के अन्धविश्वासों, रूढ़िवादी और जातिवादी ढाँचे में बदलाव आया है। ग्रामीण समाज में जितनी तीव्रता से निर्धनता और अशिक्षा का अभिशाप समाप्त हो रहा है। उतनी ही तीव्रता से गाँव विकास और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है।[4]

वर्तमान समय में ग्रामीण समाज के लोग जाति आधारित रोजगार की जगह अन्य रोजगारों कर अपनी आय के साधनों को बढ़ा रहे है। किसान आधुनिक यंत्र एवं उन्नत बीज एवं खाद का इस्तेमाल कर न केवल अपने फरालों को बढ़ा रहे हैं साथ ही अपनी आय को भी बढ़ा रहे हैं। आधुनिक समय में ग्रामीण नेतृत्व में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब जाति आधारित नेतृत्व बदल गए है। लोगों में राजनीतिक जागरूता बढ़ी है। वे न केवल अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं बल्कि ग्रामीण स्तर के चुनावों में भाग लेकर पंचायतों का नेतृत्व भी कर रहे हैं।

संदर्भ

1. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ एवं अग्रवाल (2019) : समाजशास्त्र, एस. बी. पी. डी. पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ० 87
2. मार्क्स, कार्ल (1975) : सोसायटी एण्ड सोशियल चेन्ज, यूनिवसिर्टी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो, पृ० 214
3. सिंह, वी. एन. एवं सिंह, जनमेजय (2013) : ग्रामीण समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ० 251–252
4. वही, पृ० 252–25